प्रेषक,

कुणाल शर्मा, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में.

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तराखण्ड।

देहरादून ,दिनॉक 1 7मई 2013 सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः-1 विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये सहकारिता विभाग की आयोजनागत पक्ष में जिला योजना (एस०सी०एस०पी०) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या:-406 /नियो०/जिला योजना/2013-14 दिनांक 22 अप्रैल, 2013 तथा वित्त विभाग के आदेश सं०-284/XXVII (1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 एवं आदेश सं0-329/XXVII (1)/2013 दिनांक 15 अप्रैल, 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में सहकारिता विभाग के अर्न्तगत आयोजनागत पक्ष में जिला अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित जिला योजना (एस०सी०एस०पी०) हेतु कुल ₹1,22,89,000 / - (रूपये एक करोड़ बाईस लाख नवासी हजार मात्र) की निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत व्यय हेतु निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :--

(1) इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय। प्रत्येक जनपद में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा संगत योजनाओं के लिये अनुमोदित परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा।

(2) सभी कार्यकमों की वार्षिक / मासिक लक्ष्यों का निर्धारण धनराशि के आहरण पूर्व तत्काल किया जाय तथा उक्त निर्धारित लक्ष्यों को वित्त, नियोजन विभाग को भी अवगत कराया जाय।

(3) उक्त धनराशि ऐसे किसी मद/कार्य पर धनराशि व्यय न की जाय जो योजना में स्वीकृत नहीं है, यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अलग मद में किया जाता है, तो सम्बन्धित अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(4) उक्त धनराशि का योजनावार व्यय प्रत्येक माह या अगले माह की 5 तारीख तक बी०एम0-13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग एवं शासन तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड को

भिजवाना सुनिश्चित करें।

(5) उक्त व्यय शासन के वर्तमान नियमों / निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय की उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुवल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(6) यह सुनिश्चित किया जाय कि गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय विवरण सहित शासन/महालेखाकार उत्तराखण्ड को 15 दिन के अन्दर उपलब्ध

करा दी जाय। (7) समितियों को अनुदान/राज सहायता/अंशदान दिये जाने से पूर्व सम्बन्धित नियमों, मानकों / शासनादेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।

- (8) सम्बन्धित जिलाधिकारी का यह दायित्व होगा कि उक्त धनराशि के कोषागार से आहरण के पूर्व विभागाध्यक्ष तथा शासन को विगत वित्तीय वर्ष में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए।
- 2- उक्त धनराशि को व्यय किए जाने के पूर्व वित्त विभाग के द्वारा निर्गत शासनादेश संo :- 284/XXVII (1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जाएगा ।
- 3— उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013—14 के अनुदान संख्या—30 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक 2425—सहकारिता—आयोजनागत—107—केडिट सहकारी समितियों को सहायता, 800—अन्य व्यय (लघुशीर्षक 02, 05,) तथा लेखाशीर्षक 6425 सहकारिता के लिये कर्ज 30 निवेश ऋण के अन्तर्गत संलग्नक की ग,घ,इ एवं च की पंक्तियों में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।
- 4— ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:-07(P)/XXVII-4/2013 दिनांक 14 मई, 2013 द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-आई0डी0 मूल में।

भवदीय, (कुणाल शर्मा) सचिव।

संख्या:-737 (1)/XIV-1/2013,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2. मण्डलायुक्त, गढवाल / कमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 3. निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
- 4. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5. समस्त जिला सहायक निबन्धक, उत्तराखण्ड।
- 6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
- 7. वित्त अनुभाग-4/नियोजन विभाग/समाज कल्याण अनुभाग/भाषा अनुभाग, उ० शासन।
- 8. प्रभारी, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
- प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
  - 10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से, १४२६। (रमेश कुमार) उपसचिव

## शासनादेश संख्या—737/XIV-1/13—5(7)/2013 दिनांक कि मई, 2013 का संलग्नक— वित्तीय वर्ष 2013—14 में जिला योजना (एस०सी०एस०पी०) हेतु स्वीकृत बजट के सापेक्ष जनपदों को लेखाशीर्षकवार घनराशियों के आवंटन का विवरण—

			योजना	योजना		योजना	योग	महायोग
हम io	जनपद का	योजना अनुदान संख्या-30 2425-सहकारिता आयोजनागत 107 केंडिट सहकारी समितियों को सहायता 02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान 0201-अनुसूचित जाति के सदस्यों को अंशक्य हेतु अनुदान 20-सहायक अनुदान /अंशदान/राज सहायता	अनुदान संख्या-30 2425-सहकारिता आयोजनागत 800-अन्य व्यय 02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान 20-सहायक अनुदान /अंशदान/राज सहायता	अनुदान संख्या-30 2425-सहकारिता आयोजनागत 800-अन्य व्यय 05-सहकारी कय विकययोजनान्तर्गत सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता 20-सहायक अनुदान /अंशादान / राज सहायता	योग	अनुदान संख्या—30 6425—सहकारिता के लिए कर्ज— आयोजनागत 107—जमा सहकारी समितियों को कर्ज 02— अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान 02—समितियों के सदस्य बनाने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति को ब्याज रहित ऋण 30—निवेश/ऋण	याग	40141
		η	घ	₹.		च 8	8	944
क	ন্ত	8	928	0	936	0	0	223
1.	नैनीताल	0	223	0	223	0	0	2250
2.	ऊ०सि०नगर	0	1700	550	2250	0	0	1000
3,	अल्मोडा	0	1000	0	1000	0	0	400
4.	बागेश्वर	0	400	0	400	1	1	847
5.	पिथौरागद	1	645	0	646	0	0	950
6.	चम्पावत	0	950	0	950	35	35	470
7.	देहरादून	35	400	0	435	0	0	2110
В.	हरिद्वार पीडी	0	2110	0	2110	5	5	800
9.	0.0	5	790	0	795	0	0	990
10	D. L.	0	990	0	990	0	0	726
11		0	726	0	726	0	0	779
12	X		779	0	779	- 10	49	1228
13		49	11641	550	12240	70		

र पार्क (कुणाल शर्मी) सचिव